मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये।

दो माह में ही 1.66 लाख करोड़ रू. के एमओयू धरातल पर उतरना शुरु

मुख्यमंत्री स्तर पर राइज़िंग राजस्थान में हुए एमओयू की दूसरी मासिक समीक्षा बैठक हुई

जयपुर, 12 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार "राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" के तहत हुए एमओयू को हर हाल में धरातल पर लागू करने के लिए कार्य कर रही है।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि एमओयू के क्रियान्वयन के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जाए।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 लाख 66 हजार करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू का क्रियान्वयन धरातल पर शुरू हो चुका है। एमओयू की समीक्षा के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिसके तहत 1 हजार करोड़ से अधिक राशि वाले एमओयू की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि निवेशकों से सीधा संवाद स्थापित रखा जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा इन्वैस्टर इंटरफेस के माध्यम से निवेशकों को एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भू-आवंटन से संबंधित शेष एमओयू प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। उन्होंने भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद भवानी सिंह देथा सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव उपस्थित थे।

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिये कि इन्वेस्टर इन्टरफेस के माध्यम से निवेशकों को उनके एमओयू के क्रियान्वयन पर हो रही प्रगति नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाये।**

अयोध्या राम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने शोक जताया है। आचार्य सत्येंद्र दास को कल यानी 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। सत्येंद्र दास 32 साल से रामजन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे बताया जाता है कि, 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे।

भाजपा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुघ सहित पार्टी की प्रदेश इकाई के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक में दिल्ली विधानसभा की 22 सीटों पर मिली हार के कारणों पर चर्चा हुयी।

नरेश मीणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा उप चुनाव के मतदान के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा और एसडीएम के बीच मारपीट के बाद समरावता में हुए उपद्रव के मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महेश शर्मा और हर्षिता ने अदालत को बताया कि स्थानीय गांव वाले तहसील मुख्यालय बदलने के लिए कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने मतदान का बहिष्कार भी किया था।

इस दौरान एसडीएम उनसे जबरन वोट डलवा रहे थे। इस कारण नरेश मीणा की एसडीएम से धक्का-मुक्की भी हुई, पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि पुलिस ने मामले में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास को लेकर आरोप पत्र पेश किया है। जबकि न तो उसके पास से कोई हथियार मिला और ना ही किसी को प्राण घातक चोट आई। इस घटना के बाद उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेष से एक के बाद एक आधा दर्जन मामले दर्ज किए गए। याचिका में कहा गया कि घटना को लेकर नामजद लोगों को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इनमें से कई आरोपियों को तो अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा चुका है।

रिज़र्व बैंक को आशा है कि महंगाई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ताकि इन उत्पादों को खेत से टेबल तक सही तरीके से पहुँचाया जा सके। ये भौतिक कारक उत्पादों की कीमतों पर असर डालेंगे।

हाल ही में, हमने यह भी देखा है कि सर्दी के महीनों में भी फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि पहले इन महीनों में इनकी कीमतें घट जाती थीं। रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से कुछ आंकड़े उद्धृत किए हैं, जिसमें जनवरी 2025 में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में महीने दर महीने सुधार दिखाया गया। हालांकि, इन सीमित आंकड़ों के आधार पर यह मानना कि खाद्य कीमतें स्थिर रहेंगी, शायद उचित नहीं होगा।

अन्य कीमतें अधिक जटिल हैं। कई वस्तुओं, जिसमें तेल की कीमतें भी शामिल हैं, की बुनियादी कीमतें अब वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में अधिक अस्थिर हैं। जनवरी में भारत में कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल थी, पिछले दिसंबर की तुलना में यह लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी है। यूक्रेन, गाज़ा, इज़रायल और मध्य पूर्व में स्थिति को देखते हुए, यह उम्मीद करना अवास्तविक हो सकता है कि तेल और ऊर्जा की कीमतें मध्यकाल (मीडियम टर्म) में स्थिर रहेंगी।

तथापि, हाल के महीनों में, कंज़्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा के आंकड़ों के आधार पर, रिज़र्व बैंक मानता है कि कीमतों में अगले कुछ महीनों में नरमी का रुझान दिखेगा। आर.बी.आई. के बयान में कहा गया कि, "सामान्य मानसून की उम्मीद करते हुए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 4.2 प्रतिशत अनुमानित है, जिसमें प्रथम तिमाही में 4.5, दूसरी तिमाही में 4.0, तीसरी तिमाही में 3.8, और चौथी में 4.2 प्रतिशत का अनुमान है।"

विकास की संभावना के बारे में, रिज़र्व बैंक का कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहेगा। उसने यह भी बताया कि क्षमता उपयोग (कपैसिटी यूटिलाइज़ेशन) दर 75 प्रतिशत के करीब बनी हुई है, जबकि आमतौर पर यह 73 प्रतिशत रहती है। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण में भी उज्जवल तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें अगले कुछ महीनों में मांग की स्थितियों में सुधार की संभावना जताई गई है।

हाल ही में जो बात स्पष्ट रूप से गायब रही है, वह है निजी क्षेत्र के निवेश। सरकार की बार-बार अपीलों के बावजूद, निजी क्षेत्र के निवेश कम रहे हैं। निजी क्षेत्र तभी निवेश करेगा जब उसकी क्षमता उपयोग दर (कैपैसिटी युटिलाइज़ेशन रेट) उच्च होगी और नई क्षमता निर्माण में निवेश लाभकारी होगा। निजी कंपनियां सिर्फ अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निवेश नहीं करतीं, सरकार अक्सर ऐसा कर सकती है। केवल मजबूत मांग के समर्थन से ही निजी क्षेत्र से नए निवेश की उम्मीद की जा सकती है।

उपभोक्ता खर्च के अलावा, जो घरेलू मांग को बढ़ाता है, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए निवेश और अन्य पूंजीगत खर्च भी मांग को बढ़ाते हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, केंद्रीय सरकार के पूंजीगत खर्च को 10.1 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। "प्रभावी पूंजीगत खर्च (जिसमें राज्य सरकारों को पूंजीगत खर्च के लिए अनुदान भी शामिल है) वित्तीय वर्ष के दौरान 17.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।"

ये सभी समग्र विकास को बढ़ा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग के आधार पर बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश में निर्यात उस प्रकार की भूमिका नहीं निभाते जैसी पूर्वी एशियाई देशों या चीन में निभाई थी। ऐसा लगता है कि रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार दोनों ही ग्रोथ बढ़ाने के लिए घरेलू मांग बढ़ाने पर निर्भर कर रहे हैं।

उम्मीद की जा रही है कि, केंद्रीय बजट में दी गईं बड़ी कर रियायतों के साथ ब्याज दरों में कटौती, मांग को बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यदि ये रणनीतियाँ एक साथ काम करती हैं, तो समग्र विकास दर बढ़नी चाहिए।

बंगलौर की मैट्रो का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिद्धारमैया ने कहा कि "वर्ष 2017 से टिकट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था, इसलिए बेंगलुरु मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केंद्रीय सरकार से किराया बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। अगर किराया वृद्धि राज्य सरकार के नियंत्रण में होती, तो वे हमें पत्र लिखते, न कि केंद्र को।"

भाजपा नेता मैट्रो किराया वृद्धि पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने कहा और यह भी कहा कि राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें दोनों सरकारों के अधिकारी बोर्ड में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा, यह एक स्वतंत्र संस्था है। राज्य सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। जैसे भारत में अन्य मैट्रो कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, वैसे ही भी मैट्रो रेलवे (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) एक्ट 2002 के तहत काम करता है।

कॉर्पोरेशन ने केंद्र को किराया बढ़ाने की अनुमति देने के लिए पत्र लिखा था, इसके बाद एक मूल्य पुनरावलोकन समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर थारानी ने की थी, और यह समिति सितंबर 2024 में गठित की गई थी। इस समिति ने और दिल्ली और चेन्नई मेट्रो कॉर्पोरेशंस के अधिकारियों से बातचीत की और दिसंबर 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब बैंगलूरु मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2017 से रेल किराए में फेरबदल नहीं किया है। उसके पास पहले चरण में 42.30 किमी का मेट्रो नेटवर्क था तथा 2026 तक, शहर में 175.55 किमी का मैट्रो नेटवर्क होने की उम्मीद है। मूल्य पुनरावलोकन समिति ने सभी पहलुओं की समीक्षा की और नए किराए को मंजूरी दी, मुख्यमंत्री ने कहा। सिद्धारमैया ने यह भी बताया कि दिल्ली को छोड़कर, पहले चरण में सभी मैट्रो किराए राज्य सरकार द्वारा तय किए गए थे और अब यह केंद्र द्वारा तय किए जा रहे हैं।

'केन्द्रीय सरकार ने रक्षा मंत्रालय के कायदे-कानून ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लॉबीइंग की थी ताकि वह क्षेत्र अडानी को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बनाने के लिए दिया जा सके।

ब्रिटिश अखबार के अनुसार, गुजरात सरकार ने अप्रैल 2023 में पी.एम.ओ. को पत्र लिखकर इस बारे में रक्षा मंत्रालय से बात करने की अपील की थी।

अखबार का दावा है कि, 21 अप्रैल 2023 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें डायरैक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स, गुजरात के अधिकारियों व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने शिरकत की थी।

गार्जियन के अनुसार, सैन्य अधिकारियों ने सोलर पैनल लगाने से सीमा पर टैंकों के संचालन व निगरानी प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जताई, तो उन्हें आश्वस्त किया गया कि सोलर पैनल दुश्मन के टैंक मूवमैंट के किसी भी खतरे को कम करने में सहायक होंगे। सोलर पैनल के आकार में बदलाव के अनुरोध को डैवलपर ने अस्वीकार कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार बैठक के अंत में रक्षा मंत्रालय ने पाक सीमा पर एक किलोमीटर के दायरे में सोलर पैनल और विंड टरबाइन लगाने के आपसी सहमति से किए गए निर्णय को स्वीकृति दे दी ताकि इस भूमि को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आर्थिक रुप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

अखबार के अनुसार, मोदी सरकार ने मई 2023 को सभी मंत्रालयों को सूचित कर डिफैंस प्रोटोकॉल में ढिलाई की पुष्टि की और कहा यह दिशानिर्देश भारत-पाक सीमा पर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल से लगी सीमा पर भी लागू होंगे।

द गार्जियन ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार ने पहले खावदा में 230 वर्ग किमी भूमि राज्य-चालित सौर ऊर्जा निगम को लीज़ पर दी थी। मई 2023 में निगम से यह भूमि गुजरात सरकार को लौटाने के लिए कहा गया था, जो उसने 17 जुलाई 2023 को लौटा दी। जुलाई की शुरुआत में अडानी समूह ने खावदा की भूमि में रुचि दिखाई थी।

नवम्बर में, एक अमेरिकी अभियोग ने अडानी और उनके अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी ताकि लाभकारी सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल किए जा सकें।

इन "भ्रष्ट" सौदों में अधिकांश कथित रुप से अक्षय ऊर्जा से संबंधित थे, जो अडानी के खावदा संयंत्र में उत्पन्न किए जाने थे और राज्य सरकारों को उच्च कीमतों पर बेचे जाने थे।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अडानी के खावदा संयंत्र से 7 गीगा वॉट और ऊर्जा खरीदने के लिए सबसे बड़े सौदों में से एक पर पुनः विचार करना शुरु कर दिया है, जबकि फ्रांस की कम्पनी टोटल एनर्जी, जिसने परियोजना में हिस्सेदारी के लिए 444 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था, ने समूह में आगे कोई भी निवेश नहीं करने का निर्णय लिया है।

अडानी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह सभी "संभव कानूनी उपाय" कर रहा है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908